



## जल जीवन मशिन(JJM)

### चर्चा में क्यों?

राज्य में केंद्र के प्रमुख [जल जीवन मशिन \(JJM\)](#) को लागू करने के उद्देश्य से, राजस्थान सरकार ने जल इंजीनियरों को मशिन के तहत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने और **सभी गाँवों को पाइप से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये ज़मीनी स्तर पर स्थितिकी नगिरानी करके गुणवत्ता परीक्षण करने** का निर्देश दिया है।

### मुख्य बढि:

- JJM ने वर्ष 2024 के अंत तक सभी ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति की परिकल्पना की है और गाँवों में हर घर में प्रतिव्यक्ति **55 लीटर जल की आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा** है, जहाँ लोगों को जल की कमी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
- राजस्थान में, इस मशिन के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करने की कार्य योजनाएँ प्रत्येक गाँव में **जल की उपलब्धता, वर्षा, सूखे की स्थिति, भूजल स्तर, जल संचयन, जल जनति बीमारियाँ और जल संसाधनों की स्थिति** पर आधारित हैं।
- राज्य सरकार ने ग्राम स्तरीय समितियों के सदस्यों को योजनाओं के संचालन, **जल संरक्षण, पेयजल के कुशल उपयोग और बैंक खाता संचालन के बारे में जागरूक करने के लिये प्रशिक्षण** की व्यवस्था की है।
  - ग्राम सभाओं द्वारा **प्रस्तुत और अनुमोदित ज़िला तथा ग्राम कार्य योजनाओं** ने भी विभिन्न क्षेत्रों की जल की आवश्यकताओं पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।



# जल जीवन मिशन (हर घर जल)

शुरुआत:

15 अगस्त, 2019



## उद्देश्य:

- कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) के माध्यम से वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर जल उपलब्ध कराना।

## क्रियान्वयन:

- जलशक्ति मंत्रालय: नोडल मंत्रालय
- पानी समितियाँ: गाँव में जलापूर्ति प्रणाली की योजना तैयार करना, उसका क्रियान्वयन करना, प्रबंधन और रख-रखाव करना।
- सदस्य: 10-15 (कम-से-कम 50% प्रतिशत महिलाएँ)

- गोवा तथा दादरा और नगर हवेली व दमन और दीव (D-NH and D-D) देश में क्रमशः पहले 'हर घर जल' प्रमाणित राज्य और केंद्रशासित प्रदेश हैं।

## वित्तीयन प्रतिरूप:

- केंद्र प्रायोजित योजना
  - केंद्र : हिमालयी तथा पूर्वोत्तर राज्य- 90:10
  - केंद्र : अन्य राज्य - 50:50
  - केंद्रशासित प्रदेशों के मामले में 100% केंद्र द्वारा

## प्रमुख घटक:

- बॉटम-अप प्लानिंग
- महिला सशक्तीकरण
- भविष्य की पीढ़ियों पर विशेष ध्यान
- कौशल विकास और रोजगार सृजन
- धूसर जल का प्रबंधन
- स्रोत की संधारणीयता

